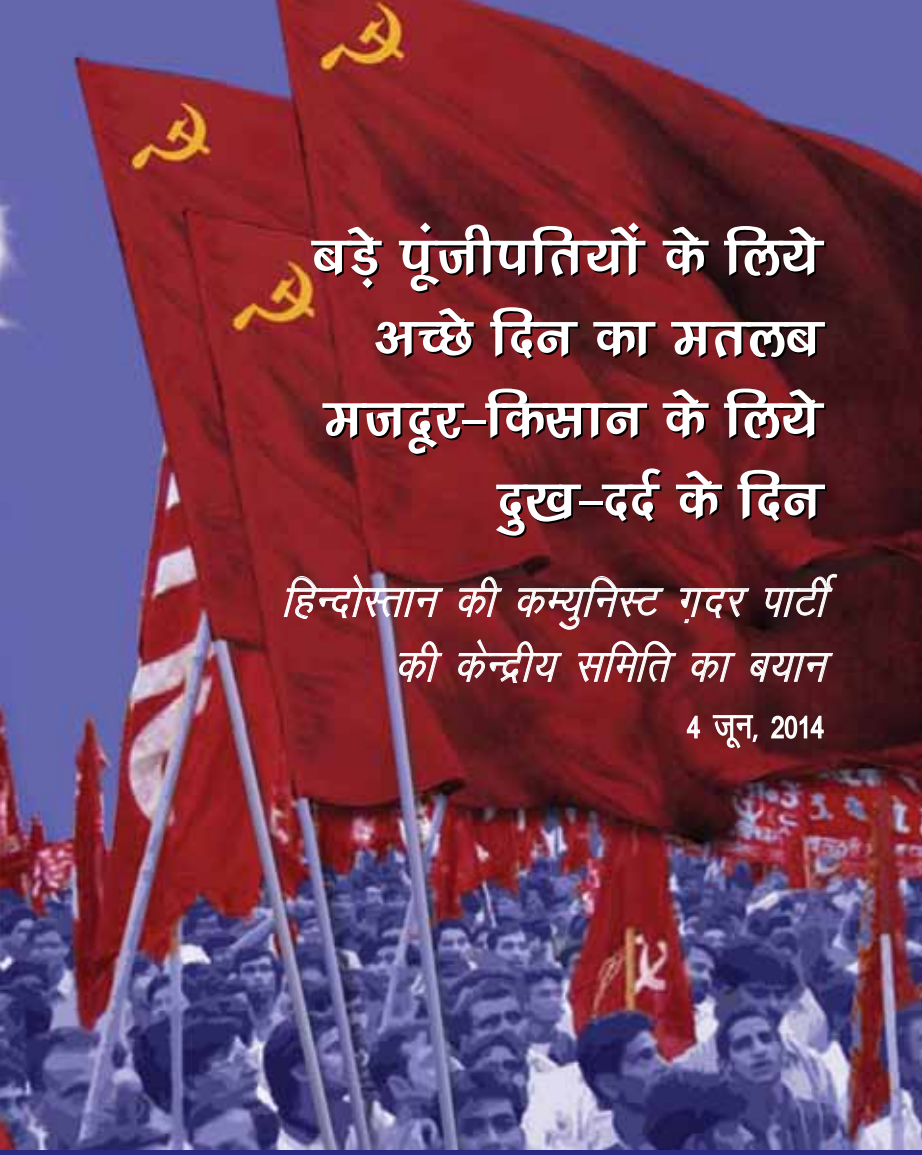

बड़े पूंजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब मजदूर-किसान के लिये दुख-दर्द के दिन

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
की केन्द्रीय समिति का बयान

4 जून, 2014

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

www.cgpi.org

बड़े पूंजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब मजदूर–किसान के लिये दुख–दर्द के दिन

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
की केन्द्रीय समिति का बयान

4 जून, 2014

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
www.cgpi.org

प्रथम प्रकाशन, जून 2014

इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को, प्रकाशक की अनुमति के साथ और स्रोत की उपयुक्त स्वीकृति सहित, अनुवादित या पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

मूल्य : 5 रुपये

प्रकाशक

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
ई–392, संजय कालोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–2
नई दिल्ली–110020, www.cgpi.org

वितरक

लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज़–2
नई दिल्ली–110020

संपर्क करें : 9868721375, lokawaz@gmail.com

प्रकाशक की टिप्पणी

यह बयान, "बड़े पूंजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब मजदूर–किसान के लिये दुख–दर्द के दिन", हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति की 31 मई, 2014 को सम्पन्न हुई परिपूर्ण सभा में हुए विचार–विमर्श और मूल्यांकन पर आधारित है।

बड़े पूंजीपतियों के लिये अच्छे दिन का मतलब मजदूर–किसान के लिये दुख–दर्द के दिन

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का बयान, 4 जून, 2014

"सबका साथ, सबका विकास!" इस नारे के साथ, नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भाजपा केन्द्र में सत्ता में आई है। उसने 52 प्रतिशत सीटों पर कब्ज़ा कर लिया है और संसद में कांग्रेस पार्टी की अब बहुत कम संख्या रह गयी है। अब हमें कहा जा रहा है कि "अच्छे दिन आ गये हैं"!

क्या यह भाजपा–नीत राजग सरकार एक आधुनिक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था स्थापित करेगी, जिससे सभी के लिये मुनासिब दाम पर, उपभोग की सभी जरूरी वस्तुयें उपलब्ध होंगी? क्या इसे सुनिश्चित करने के लिये यह सरकार

विदेशी व्यापार और थोक व्यापार पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करेगी?

क्या यह सरकार सुनिश्चित करेगी कि मजदूरों के वेतन हमेशा जीने के खर्च से ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे? क्या यह सरकार बिना कोई अपवाद किये, प्रत्येक मजदूर के लिये जीने योग्य वेतन और पेंशन सुनिश्चित करेगी? क्या यह सुनिश्चित करेगी कि किसी मजदूर को प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर न किया जाये? क्या यह मजदूरों के अपनी पसंद के यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकार की हिफाज़त करेगी? क्या यह सरकार जेल में बंद मारुति के मजदूरों को फौरन रिहा करेगी?

क्या यह सरकार रोज़गार की असुरक्षा को दूर करेगी, जिसकी वजह से हमारे लाखों किसान भाई–बहन खुदकुशी करने को मजबूर हुये हैं? क्या यह जरूरी सरकारी निवेश करेगी ताकि सिंचाई का पानी, बीज, उर्वरक, बिजली और अन्य आवश्यक चीजें किसानों को स्थायी व मुनासिब दामों पर उपलब्ध हों? क्या यह सभी कृषि उत्पादों के लिये स्थायी व लाभदायक दाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एक भरोसेमंद सार्वजनिक विपणन व्यवस्था स्थापित करेगी?

क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह भाजपा–नीत राजग सरकार सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास दिलायेगी?

क्या यह सरकार कर्जे चुकाने में, फौजीकरण करने में तथा पूंजीपतियों को टैक्स छूट देने में सार्वजनिक धन के अनुत्पादक खर्च पर रोक लगायेगी, जिसके बिना केन्द्र सरकार के पास, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास देने के लिये पर्याप्त धन नहीं होगा?

यह सरकार इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती है, न ही करेगी, क्योंकि यह टाटा, अंबानी, बिरला और दूसरे इजारेदार घरानों तथा विदेशी पूंजीनिवेशकों के अधिकतम मुनाफों को सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध है।

मजदूरों और किसानों के मिले–जुले श्रम से ही प्रति वर्ष सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद बनता है। हमारे श्रम से उत्पन्न मूल्य का अधिक से अधिक हिस्सा पूंजीपति वर्ग वैध और अवैध मुनाफों के रूप में, निचोड़कर अपनी जेबों में डाल लेता है। अधिक से अधिक मुनाफों के लिये इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने का मतलब है मजदूरों का और तेज़ी से शोषण करना, किसानों, आदिवासियों, आदि को और ज्यादा लूटना। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का मतलब है सस्ते से सस्ते दामों पर हमारे श्रम और कुदरती संसाधनों को मुहैया कराना।

क्या यह सरकार हरेक हिन्दोस्तानी नागरिक के जमीर के अधिकार की रक्षा करेगी? क्या यह आतंकवाद से लड़ने के

नाम पर, हर प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न और मनमानी से की गई गिरफ्तारियों को रोकेगी? क्या यह 1984, 1992–93 और 2002 के साम्प्रदायिक हत्याकांडों के गुनहगारों को सज़ा देगी? क्या यह महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा से सुरक्षा देगी? क्या यह अपने ही लोगों के खिलाफ़ सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रयोग, जैसा कि कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, को समाप्त करेगी? क्या यह सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम और अवैध गतिविधि विरोधक अधिनियम जैसे फासीवादी कानूनों को हमेशा के लिये रद्द कर देगी?

हम इस सरकार से इन सब कार्यों की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि यह वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और राज्य की हिफ़ाज़त करने को वचनबद्ध है, जो पूरी तरह दमनकारी, पिछड़ा व साम्प्रदायिक है। ऐतिहासिक अनुभव ने यह दिखाया है कि दोनों भाजपा और कांग्रेस पार्टी, शासक वर्ग के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के इरादे से, धर्म, राष्ट्रीयता और जाति के आधार पर लोगों को उत्पीड़ित करने तथा आपस में भिड़ाने के लिये राज्य का इस्तेमाल करने की कला में माहिर हैं। साम्प्रदायिक हिंसा और राजकीय दमन पूंजीपति वर्ग को अपना शोषण का राज चलाने में सहायता देते हैं।

जिस वर्गों में बंटे हुये समाज में हम रहते हैं, इसमें किसी भी सरकार को या तो इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग की सेवा करनी पड़ेगी या फिर मजदूर वर्ग की

अगुवाई में मेहनतकश जनसमुदाय की सेवा करनी पड़ेगी। उसे या तो पूंजीवादी व्यवस्था और वर्तमान राज्य की हिफ़ाज़त करनी पड़ेगी या क्रान्ति के द्वारा उनका तख्तापलट करने के लिये काम करना पड़ेगा।

भाजपा–नीत राजग सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह पूंजीपति वर्ग के लिये अच्छे दिनों की गारंटी देने को वचनबद्ध है, यानि कि मजदूरों और किसानों की रोजी–रोटी और अधिकारों पर और ज्यादा हमले करने को वचनबद्ध है।

"सब के लिये विकास" के साथ–साथ, मोदी, के अभियान में परिवर्तन का भी वादा किया गया था। परन्तु नयी सरकार के कुछ शुरुआती कदमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका कार्यक्रम वही पूंजीवादी सुधारों का कार्यक्रम है।

नये नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह संकेत दिया है कि वह जल्दी ही एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने के कदम लेंगे। नये पर्यावरण और वन मंत्री को आदेश दिया गया है कि खनन, इस्पात और ऊर्जा क्षेत्रों में पूंजीपतियों की परियोजनाओं के अधिक से अधिक प्रस्तावों को इजाज़त दे दी जाये, जिन्हें पर्यावरण संबंधी चिंताओं या आदिवासी समुदायों के विरोध के कारण अब तक रोक कर रखा गया था।

भूमि अधिग्रहण के विवादास्पद सवाल पर, कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार की पहल से लोक सभा में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम पास किया गया था, भाजपा उसका समर्थन करती है। इस अधिनियम के तहत सरकार को बलपूर्वक किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने और उसे पूंजीवादी कंपनियों के हाथों में सौंपने की पूरी छूट दी जाती है, बेशक उस भूमि पर फसल उगाई जा रही हो।

दूसरे शब्दों में, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। मेहनतकश जनसमुदाय और प्राकृतिक पर्यावरण की लूट–खसौट के जरिये बड़े पूंजीपतियों की अमीरी को बढ़ाने की उसी चलती आ रही नीति व कार्यक्रम को लागू करने को यह सरकार वचनबद्ध है। भाजपा का "सब के लिये विकास" का नारा कांग्रेस पार्टी के "समावेशी विकास" के नारे से भिन्न नहीं है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं। वे एक ही वर्ग के हितों के प्रतिनिधि हैं। वे अपने प्रचार में उन सब बातों को कहती हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, परन्तु जब वे सत्ता में होती हैं तब बड़े पूंजीपतियों, जिनके दिये गये धन से उनका काम–काज चलता है, के हितों के अनुसार ही काम करती हैं।

बड़े पूंजीपति एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो यह सुनिश्चित करेगी कि मजदूर वर्ग के अधिकतम शोषण और किसानों, कारीगरों व आदिवासी समुदायों की अधिकतम लूट के जरिये,

पूंजीपतियों की हवस और वैश्विक विस्तार की आकांक्षायें निर्विरोध पूरी हों।

हमारे समाज की मूल समस्या यह है कि सामाजिक उत्पादन की पूरी प्रक्रिया पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफों की लालच से प्रेरित है। उत्पादन के मुख्य साधन, खदान और फैक्टरी, विनिमय के साधन, यातायात और संचार, सब पूंजीवादी कंपनियों के हाथों में हैं। उत्पादक पूंजीनिवेश सिर्फ उस समय और उन क्षेत्रों में किये जाते हैं, जब और जहां बड़े पूंजीपतियों को अधिकतम मुनाफे मिल सकते हैं। जब अधिकतम मुनाफे नहीं मिलते हैं तो पूंजीपति अपनी पूंजी को सट्टेबाज़ी और दूसरी परजीवी कार्यवाहियों में लगाते हैं।

निजी धन इतना संकेंद्रित है कि इजारेदार पूंजीपति सभी सार्वजनिक मामलों पर हावी हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वह हमेशा अधिकतम मुनाफे बना सकें। इसके लिये सरकार ढेर सारा धन खर्च करती है, "सार्वजनिक कर्जा" बढ़ाती रहती है और अपने घाटे को पूरा करने के लिये, तरह–तरह के टैक्सों तथा मुद्रास्फीति के जरिये, लोगों पर आर्थिक बोझ को बढ़ाती रहती है।

अगर सभी मेहनतकशों के लिये अच्छे दिन लाना है तो हमारे जीवन स्तर और उत्पादक क्षमता पर निवेश करना आवश्यक है। इस प्रकार के निवेश को सुनिश्चित करने के लिये, उत्पादन

और विनिमय के मुख्य साधनों को सामाजिक सम्पत्ति में बदलना आवश्यक है। वित्त और व्यापार का राष्ट्रीयकरण और सामाजीकरण करने की फौरी व सख्त जरूरत है। एक सार्वजनिक विपणन व्यवस्था से जुड़ी हुई आधुनिक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की स्थापना करने के लिये ये कुछ आवश्यक कदम हैं।

यह ज़ाहिर है कि पूंजीपतियों द्वारा समर्थित कोई भी पार्टी ऐसे कदम नहीं लेगी, जिनका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को मानवीय जरूरतें पूरी करने की दिशा में चलाना, न कि पूंजीवादी लालच पूरी करने की दिशा में। अर्थव्यवस्था को ऐसी नई दिशा दिलाने के लिये, यह आवश्यक है कि मजदूर वर्ग, किसानों और समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों व तबकों के साथ गठबंधन बनाकर, राज्य सत्ता को अपने हाथों में ले। इसके लिये लोकतंत्र की व्यवस्था और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन लाने की जरूरत है।

हम मेहनतकश समाज में बहुसंख्या में हैं परन्तु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में समाज की दिशा को तय करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया से लेकर, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर अलग–अलग पूंजीवादी समूहों द्वारा समर्थित पार्टियां हावी हैं। समय–समय पर होने वाले चुनावों का इस्तेमाल करके बड़े–बड़े पूंजीपति किसी एक पार्टी को, जो बदनाम हो चुकी है, बदलकर उसकी जगह पर किसी

दूसरी पार्टी को बिठाते हैं, ताकि लोगों को बुद्धू बनाया जा सके और पूंजीपतियों की अमीरी बढ़ाने का कार्यक्रम आगे बढ़ सके। 21 प्रतिशत मतदाताओं से वोट पाकर एक राजनीतिक पार्टी संसद में 52 प्रतिशत सीटों पर कब्ज़ा कर सकती है, जैसा कि भाजपा ने अबकी बार किया है।

लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था वास्तव में पूंजीपतियों का अधिनायकत्व है। वह मजदूरों, किसानों और अन्य मेहनतकशों पर अल्पसंख्यक शोषकों का राज है। पूंजीपति मतपेटी और बंदूक की गोली, दोनों से राज करते हैं। हमें ऐसे परिवर्तन की जरूरत है, जिसमें वर्तमान व्यवस्था की जगह पर एक उन्नत व्यवस्था स्थापित होगी, जिसमें मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश शासक होंगे तथा राज्य उनके अधिकारों की हिफ़ाज़त करेगा। हमें ऐसे राज्य और राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लोग संप्रभु हैं और चुने गये निकाय जनता के नियंत्रण में हैं।

हमें एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है जिसमें उम्मीदवारों के चयन में पार्टियों की प्रधानता न हो, जिसमें धन बल के प्रयोग से सभी निर्वाचित निकाय अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों से भरे हुये न हों। मजदूरों और किसानों को अपने सर्वोत्तम प्रतिनिधियों का चयन करके उन्हें उच्चतम फैसलाकारी निकायों में पहुंचाने तथा देश का अजेंडा तय करने में भाग लेने की क्षमता होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था में किसी

भी राजनीतिक पार्टी का फर्ज होगा मेहनतकश बहुसंख्या को राज करने में सक्षम बनाना।

मजदूरों और किसानों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में फैसले लेने की पूर्ण ताकत नहीं सौंप देनी चाहिये, जैसा कि इस समय होता है। मजदूरों और किसानों में यह क्षमता होनी चाहिये कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहरा सकें तथा किसी भी समय वापस बुला सकें। मजदूरों और किसानों को कानून बनाने व बदलने तथा संविधान को फिर से लिखने का अधिकार होना चाहिये।

हमें एक नया संविधान बनाने की जरूरत है जो जनता की संप्रभुता और मानव अधिकारों, जनवादी व राष्ट्रीय अधिकारों की अलंघनीयता की गारंटी देगा। हमें मजदूरों और किसानों के नये राज्य और सरकार की जरूरत है। वर्तमान व्यवस्था के इसी विकल्प की जरूरत है।

पूंजीपतियों के अधिनायकत्व की जगह पर श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व, यानि मेहनतकश बहुसंख्या का राज स्थापित करना होगा। सिर्फ मेहनतकशों की नई राज्य सत्ता ही अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है, यह सुनिश्चित करने के लिये कि श्रम करने वालों का आदर हो और वे अपने सम्मिलित श्रम से उत्पन्न दौलत का आनंद उठा सकें। तब

हिन्दोस्तानी समाज नई नींव पर, एक आधुनिक सभ्य समाज बतौर उठ खड़ा होगा।

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी वर्तमान व्यवस्था का पर्दाफाश करने और क्रांतिकारी परिवर्तन के कार्यक्रम के इर्द–गिर्द राजनीतिक एकता बनाने के लिये चुनाव के मंच का इस्तेमाल करती है। हाल के चुनावों में हमने एक घोषणापत्र के सहित भाग लिया था, जिसमें हमने हिन्दोस्तानी गणराज्य का पुनर्गठन करने और सभी की जरूरतें पूरी करने के लिये अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के वैकल्पिक कार्यक्रम को बहादुरी से पेश किया। हम यह मानते हैं कि अगर मेहनतकशों की सभी पार्टियां व संगठन इस कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एकजुट हो जायें तो राजनीतिक मंच पर एक क्रान्तिकारी विपक्ष दल उभर कर आयेगा।

हमारा लक्ष्य सिर्फ "कांग्रेस मुक्त भारत" नहीं है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा हिन्दोस्तान जो पूंजीपति वर्ग के शासन से मुक्त हो, शोषक आर्थिक व्यवस्था और उसे कायम रखने वाली दमनकारी राज्य से मुक्त हो। मजदूरों और किसानों के शासन से देशी और विदेशी पूंजी द्वारा हमारी भूमि व श्रम का शोषण और लूट समाप्त होगा। उपनिवेशवाद, सामंतवाद और जातिवादी ऊंच–नीच की प्रथा के सारे अवशेष मिट जायेंगे।

हम मजदूर वर्ग के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि हमारी पार्टी में जुड़ें और क्रांति और समाजवाद के लक्ष्य के लिये

काम करें! आइये श्रमजीवी वर्ग संघर्ष के हिरावल दस्ते को मजबूत करें!

हम सभी कम्युनिस्टों, चाहे वे किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हों, से आह्वान करते हैं कि शासक पूंजीपति वर्ग और उसके समाज–विरोधी कार्यक्रम को चुनौती देने के लिये, संयुक्त मजदूर–किसान विरोध को एक क्रांतिकारी राजनीतिक मोर्चा बतौर गठित करने पर अपनी पूरी ताकत केंद्रित करें। संपूर्ण शोषित और उत्पीड़ित जनसमुदाय को अगुवाई देने वाले, राजनीतिक तौर पर एकजुट मजदूर वर्ग को नेतृत्व देने के लिये, हम कम्युनिस्टों की एकता पुनः स्थापित करने की दिशा में काम करें।

हम सभी मजदूरों और किसानों, महिलाओं और नौज़वानों के यूनियनों और संगठनों से आह्वान करते हैं कि जनता को संप्रभु बनाने के लिये, राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने तथा सभी की जरूरतें पूरी करने के लिये अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एकजुट हों!

आइये, हम मजदूरों और किसानों का राज स्थापित करने तथा हमारे समाज की सबतरफा प्रगति का रास्ता खोलने की तैयारी करें ताकि हमारी जनता के लिये वास्तव में अच्छे दिन आयें!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा हाल में प्रकाशित किये गये दस्तावेज़

घोषणा पत्र 2014

लोक सभा चुनाव 2014 के अवसर पर मजदूर वर्ग के कार्यक्रम व दिशा पेश करने वाला घोषणा पत्र

हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी और तमिल भाषा में उपलब्ध

मूल्य 10 रूपया

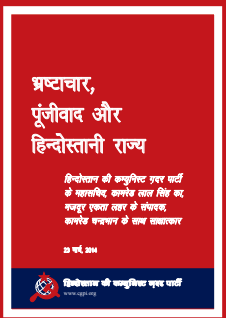

भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और हिन्दोस्तानी राज्य

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह से साक्षात्कार

हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी और तमिल भाषा में उपलब्ध, मूल्य 10 रूपया

महिलाओं की मुक्ति के लिये संघर्ष को आगे बढ़ायें!

महिला मुक्ति के विषय पर सन 2000 से 2013 तक, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा जारी बयानों का संकलन

हिन्दी और अंग्रेजी में उपलब्ध, मूल्य 50 रूपया

कृपया मंगवाने के लिये संपर्क करें :- 392 संजय कालोनी, ओखला फेस - 2, नई दिल्ली 110020 फोन - 09868721375, lokawaz@gmail.com